www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 313 | जौनपुर शनिवार, 04 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

राम मंदिर चढ़ावा विवाद की निष्पक्ष जांच हो : मनीष तिवारी

चंडीगढ़, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राम मंदिर चंदा मामले को लेकर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान समेत कई मामलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित गबन के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। राजनीति उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि वहां कथित गबन हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। यह मामला करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह रामलला के जन्मस्थान का विषय है, जिसकी अपनी पवित्रता है। उस पवित्रता को बनाए रखना और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है। जो भी घटनाक्रम वहां हुआ है, उसकी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और लोगों का विश्वास कायम रहे। महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाए जाने की घोषणा पर मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, कॉमन सिविल कोड की नहीं। पिछली बार जब इस विषय पर चर्चा हुई थी ।

होर्मुज स्ट्रेट से फ्रांस ने हटाया अपना विमानवाहक पोत

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि फ्रांसीसी विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल अब मध्य पूर्व से अपने घरेलू बंदरगाह टूलॉन लौट रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, इस विमानवाहक पोत को फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में होर्मुज स्ट्रेट में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मिशन की तैयारी के लिए क्षेत्र में भेजा गया था। मैक्रों ने अपने पोस्ट में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसी वजह से फ्रांस ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी में बदलाव करने का फैसला किया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्रांस के बारूदी सुरंग हटाने वाले संसाधन और उनके सुरक्षा बेड़े वहीं तैनात रहेंगे और जरूरत पड़ने पर सहयोगी देशों के साथ अभियान चलाने के लिए तैयार रहेंगे। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि चार्ल्स डी गॉल फिलहाल भूमध्य सागर में मौजूद है। फ्रांस और ब्रिटेन ने अप्रैल के मध्य में घोषणा की थी कि वे होर्मुज स्ट्रेट में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा एस्कॉर्ट मिशन का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद मई में फ्रांस ने इस अभियान की तैयारी के लिए चार्ल्स डी गॉल को मध्य पूर्व भेजा था,।

भारत की डिप्लोमेसी का असर, संकट के समय 40 से ज्यादा देशों से आया ईंधन - पीएम मोदी

जयपुर, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी– सह–पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए कहा कि इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ दोस्ती बहुत काम आई। प्रधानमंत्री मोदी ने पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। हालांकि, सही फैसले, सटीक आकलन, प्रभावी रणनीति और कूटनीतिक शक्ति का सकारात्मक इस्तेमाल करके भारत संकट से उबर पाया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के समय में भारत की दूसरे देशों के साथ दोस्ती बहुत काम आई। उन्होंने कहा, जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत 25–26 देशों से ईंधन का आयात करता था, लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। इसी बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर ईंधन संकट के बीच अफवाह फैलाने और राजनीतिक खेल खेलने के आरोप लगाए। विपक्ष पर इशारों–इशारों पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, ष्बहुत अफवाएं फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए। लेकिन जिनके इरादे गलत थे, वो सफल नहीं हो पाए।

नितिन नबीन का लखनऊ में स्वागत, रोड शो में बरसे फूल

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक 18 किलोमीटर लंबे रोड शो में 42 से अधिक स्थानों पर अभिनंदन होगा। स्वागत के लिए हजारों कार्यकर्ता और व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी एवं सभी अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि प्रभु श्रीराम एवं लीलाधारी भगवान श्रीकृष्ण के चरणरज से पावन हुई संस्कृति, संस्कार और सृजन की साधना स्थली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने वालों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्षध्केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी, एके शर्मा, संजय सेठ, ब्रजलाल, महापौर सुषमा खर्कवाल समेत अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि व संगठन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्र किया जमा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अपना विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा किया। इस दौरान उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और चुनाव अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने निर्वाचन अधिकारियों के साथ

उपराष्ट्रपति भवन पहुंचकर दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रक्रिया में सहायता की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने अपना भरा हुआ गणना प्रपत्र निर्वाचन अधिकारियों को सौंपा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सटीक और अद्यतन मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता की भागीदारी से ही निर्वाचन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रभावी बन सकती है। उपराष्ट्रपति ने सभी पात्र मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से चुनाव अधिकारियों को पूरा सहयोग देने और इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार : अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 23 और व्यक्तियों को गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार भारत और देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू–कश्मीर (पीओके) से

भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 खूंखार आतंकवादियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमलों, आतंकवाद को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकी संगठनों की मदद, फंड जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। मोदी सरकार भारत और देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है।" गृह मंत्रालय के अनुसार, इन व्यक्तियों को औपचारिक रूप से आतंकवादी घोषित किए जाने से उनके वित्तीय नेटवर्क, आवाजाही, भर्ती क्षमता और आतंकवाद समर्थित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही यह कदम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल तत्वों के लिए कड़ा संदेश भी होगा। इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वित कानूनी, जांच और निवारक कार्रवाई ।

पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए केंद्र ने राज्यों के साथ बनाई कार्ययोजना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला में सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राज्यों से स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) के संकलन पर विशेष ध्यान देने और प्रदर्शन–आधारित अनुदानों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने का आग्रह किया। कार्यशाला में केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

भी मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यशाला में 18 राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों ने भाग लिया, जबकि अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व संबंधित पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज, अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी समेत मंत्रालय और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यशाला का आयोजन सोलहवें वित्त आयोग (2026–31) की उन सिफारिशों के संदर्भ में किया गया, जिनमें वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 4,35,236 करोड़ रुपए के वित्तीय हस्तांतरण की अनुशंसा की गई है। साथ ही वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कार्यान्वयन की रूपरेखा स्थानीय शासन की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ताकि पंचायती राज संस्थाएं अधिक सशक्त और वित्तीय रूप से सक्षम बन सकें। कार्यशाला के दौरान पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुक्ता शेखर ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें पंद्रहवें वित्त आयोग के दौरान हुए प्रदर्शन की समीक्षा, सोलहवें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी परिचालन दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई।

महाकाल से अयोध्या पदयात्रा– दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान

भोपाल, (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने घोषणा की कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में पारदर्शिता की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक एक गैर–राजनीतिक पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए अपने दान का हिसाब मांगने के लिए वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर उज्जैन में सरकारी जमीन आवंटन को लेकर लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि यह राजनीति नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। 79 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पदयात्रा 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को उज्जैन के महाकाल मंदिर से शुरू होगी और अयोध्या में समाप्त होगी।उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में अदालत में एक मामला भी दायर करेंगे और यह जानकारी मांगेंगे कि राम मंदिर के लिए मिले दान का उपयोग किस प्रकार किया गया। उनकी यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राम मंदिर में दान और कीमती सामान की कथित चोरी के आरोपों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है। भोपाल स्थित अपने आवास के बाहर श्भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे और दान की चोरी करने वालों का प्रवेश वर्जित है लिखा ।

एकनाथ शिंदे की अचानक बिगड़ी तबीयत, ठाणे के निजी अस्पताल में भर्तीय सभी कार्यक्रम रद्द

पुणे, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार राजनीतिक गतिविधियों, विधानमंडल सत्र और सार्वजनिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा। अस्पताल सूत्रों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।जानकारी के मुताबिक, एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों, सरकारी कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान भी उन्हें बुखार और कमजोरी महसूस हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने कुछ निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने पर सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करने पड़े।राजनीति समाचार पत्र डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक थकान, वायरल संक्रमण और पर्याप्त आराम नहीं मिलने के कारण उनकी तबीयत प्रभावित हुई। प्रारंभिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की सलाह दी।एकनाथ शिंदे के अस्पताल में भर्ती होने का असर शुक्रवार को होने वाले कई राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी पड़ा। ठाणे के गंगूबाई शिंदे हॉल में शिवसेना की नेता शुभांगी पाटिल के पार्टी प्रवेश का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। बाद में देर रात कल्याण से सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में शुभांगी पाटिल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। वर्ष 2022 में शिवसेना में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उन्होंने अलग गुट का नेतृत्व किया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बने। बाद में 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार में उन्होंने उपमुख्यमंत्री का पद संभाला। वर्तमान में वे शिवसेना के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल की नई पुस्तक ब्रिजिग बॉर्डर्स का भव्य लोकार्पण किया गया - इस पुस्तक से वैश्विक वित्तीय चुनौतियों का होगा सरल व्यावहारिक समाधान

ब्यूरो चीफध्सत्य प्रकाश उपाध्याय

नई दिल्ली । नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, कमलादेवी कॉम्प्लेक्स स्थित मल्टीपर्पज हॉल में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं अमेरिका के एनरोल्ड एजेंट सीए विनोद रावल की नई पुस्तक "Bridging Borders – Taxation, Repatriation - amp; Succession" का भव्य लोकार्पण आयोजित किया गया । इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और विशेषज्ञ मौजूद रहे। सीमा–पार वित्तीय और कर संबंधी विषयों पर केंद्रित है पुस्तक यह पुस्तक विशेष रूप से एनआरआइ, प्रवासी भारतीयों, वैश्विक स्तर पर जुड़े भारतीय परिवारों, चार्टर्ड

अकाउंटेंट, टैक्स सलाहकारों और वित्तीय पेशेवरों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसमें सीमा–पार कराधान, विदेश से धन की वापसी , उत्तराधिकार योजना , विरासत और विभिन्न देशों के नियामकीय अनुपालन जैसे जटिल विषयों को सरल, व्यावहारिक और उदाहरणों के साथ समझाया गया है। वैश्विक वित्तीय चुनौतियों का मिलेगा व्यावहारिक समाधान पुस्तक का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों से जुड़े परिवारों को कर, संपत्ति प्रबंधन और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनी एवं वित्तीय पहलुओं की बेहतर समझ प्रदान करना है। लेखक ने अपने पेशेवर अनुभव के आधार पर ऐसे समाधान प्रस्तुत किए हैं, जो पाठकों को सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेंगे। इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं । कार्यक्रम में पुस्तक के विषयों और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा की गई ।

संपादकीय

छवि से बंध जाना सही सोच नहीं

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का अपना महत्त्व है। इसलिए उन पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन कृत्रिम ढंग से उनमें दर्जा बढ़ाने की कोशिशें हानिकारक हैं। फिर रैंकिंग्स में उभरने वाली छवि से बंध जाना सही सोच नहीं है। यह अच्छी खबर है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। 500 विश्वविद्यालयों की इस ताजा सूची में भारत की 54 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई हैं। इसमें भारत की नुमाइंदगी अब आईआईटी या आईआईएस जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों तक सीमित नहीं रह गई है। बल्कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राज्यों के विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्थानों ने भी इसमें जगह बनाई है। हालांकि यह अप्रिय तथ्य अब भी कायम है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। टॉप 200 में भारत के सिर्फ तीन विश्वविद्यालय ही आए हैं। सबसे ऊपर 118वें स्थान पर आईआईटी दिल्ली आई है। बहरहाल, शिक्षा संस्थानों के स्तर को जानने के लिए रैंकिंग्स भले एक प्रचलित माध्यम हों, लेकिन इनके आधार पर किसी देश में शिक्षा की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना सही नजरिया नहीं होगा। मसलन, क्यूएस रैंकिंग की यह एक बड़ी आलोचना है कि इसमें विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रतिष्ठा को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। इसका भार 40 प्रतिशत तक है। प्रतिष्ठा मनोगत पैमाना है, जो सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों की जानकारी एवं पूर्व–धारणाओं से तय होती है। एक अन्य पैमाना विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की उपस्थिति है। भारतीय विश्वविद्यालय इस पैमाने पर पिछड़ जाते हैं। इसलिए क्यूएस या ऐसी अन्य रैंकिंग्स में भारत की स्थिति अपने–आप में समस्या नहीं है। समस्या यूनिवर्सिटी शिक्षा तक सीमित वर्गों की पहुंच, वास्तविक अनुसंधान पर कम ध्यान, और जाने वाली शिक्षा का रोजगार बाजार से कमजोर संबंध हैं। इस ओर ध्यान देने के बजाय रैंकिंग में आगे बढ़ने की होड़ का खराब असर यह हुआ है कि विश्वविद्यालयों में प्रति फैकल्टी प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने और उन प्रकाशनों का आपस में उद्धरण देने जैसी विकृतियां उभरी हैं। इसलिए आवश्यकता रैंकिंग्स से आगे सोचने की है। इसके लिए उच्च शिक्षा के लिए जीडीपी का अधिक हिस्सा आवंटित करना, शिक्षक–छात्र अनुपात सुधारना और शोध संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। वैश्विक शोध नेटवर्क से जुड़ने और संकाय आदान–प्रदान को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। रैंकिंग्स को पूरी तरह ठुकराना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसमें उभरने वाली छवि से बंध जाना सही सोच नहीं है।

सीजेपी के आंदोलन के पीछे साजिश

अजीत द्विवेदी

जिसको देखिए वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पर संदेह कर रहा है। उससे जुड़े लोगों की पृष्ठभूमि खोजी जा रही है। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक समय में नरेंद्र मोदी का प्रशंसक था किसी के बारे में जानकारी दी जा रही है और वह आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल करता था। किसी को राहुल गांधी का विरोध करने वाला बताया जा रहा है तो किसी को ब्राह्मण विरोधी ठहराया जा रहा है। सोचें, युवाओं का एक समूह इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा उठा कर सरकार के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। लेकिन जरूरी मुद्दे उठाने में असफल रहे लोग उनकी पृष्ठभूमि निकाल कर उनको निशाना बना रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और तीनों प्रवक्ताओं सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका की पृष्ठभूमि खोज कर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम इन लोगों को युवाओं व छात्रों का एजेंडा हाईजैक करने के लिए भाजपा की ओर से प्लांट किया गया बता रहे है तो भाजपा के नेता सीजेपी की तुलना अन्ना हजारे व अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से कर रहे हैं और इसे अर्बन नक्सल समूह कह रहे हैं। सवाल है कि इस समूह और इसके आंदोलन को वर्तमान हालात से पैदा हुए असंतोष और युवाओं की बेचैनी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्यों नहीं माना जा सकता है? यह मानने में क्या समस्या है कि आज किशोर और युवा परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों और नौकरी व रोजगार की घटती संभावनाओं की वजह से परेशान हैं और इसलिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला तो वे वहां से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं? अभिजीत दीपके या सीजेपी से जुड़े दूसरे लोगों ने किशोरों और युवाओं को अपनी नाराजगी और असंतोष जाहिर करने का एक मंच दिया है, जहां से वर्तमान समय की सबसे ज्वलंत समस्या को उठा रहे हैं। सीजेपी के लोग पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुचिता बहाल करने की मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इन मांगों से भला विपक्ष की पार्टी या नेता को क्या समस्या हो सकती है? युवाओं का यह समूह भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को भी निशाना बना रहा है। इसलिए आप इसे सांप्रदायिक भी नहीं कह सकते हैं। तभी सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीजेपी के आंदोलन को विपक्ष, खास कर कांग्रेस पार्टी अपनी विफलता के तौर पर देख रही हो और इस वजह से इनको निशाना बनाया जा रहा हो? यह संभव है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पर इस तरह का कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकी इसलिए सीजेपी को मौका मिला। अगर कांग्रेस युवाओं के असंतोष को आवाज दे रही होती और उस असंतोष को प्रकट करने का मंच दे रही होती तो शायद सीजेपी जैसे किसी समूह की जरुरत नहीं पड़ती। ध्यान रहे सीजेपी अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बना एक अकाउंट भर है। उसके पास न कोई संगठन है, न कोई बड़ा चेहरा है और न किसी राजनीतिक अभियान को चलाने का प्रशिक्षण या अनुभव है। फिर भी उस मंच से करोड़ों युवा जुड़े और उसके आह्वान पर हजारों लोग 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। कहने को कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट लिखी और प्रभावित छात्रों से मुलाकात की लेकिन यह समझने की जरुरत है कि समस्या जितनी बड़ी है उसके मुकाबले कांग्रेस का प्रयास बहुत छोटा और सुविधाजनक है। ड्राइंग रूम में बैठ कर 18 साल के छात्र से बात करना और उसकी वीडियो साझा करके सरकार पर हमला करना बहुत आसान है। बहरहाल, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए लोगों की संख्या असल में कितनी थी, किसके साथ ज्यादा भीड़ आई, किसका भाषण कैसा हुआ, कितनी देर प्रदर्शन चला, कौन जल्दी चला गया, किसको गर्मी लग रही थी और किसको एसी में बैठना था इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जंतर मंतर पर यह तस्वीर दिखी कि हजारों लोग इकट्ठा हुए, जिनमें परीक्षा की गड़बड़ियों और पेपर लीक से परेशान छात्र थे तो नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवा भी थे और रोजगार की घटती संभावना से बेचैन अधेड़ लोग भी थे। मुख्यधारा की मीडिया ने भले इसका बहिष्कार किया लेकिन राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के तमाम छोटे बड़े यूट्यूबर वहां मौजूद थे। उन्होंने इसे अपने अपने हिसाब से कवर किया और देश के हर हिस्से में करोड़ों लोगों ने इसे देखा। किसी राजनीतिक या सामाजिक घटनाक्रम में लोगों में ऐसी उत्सुकता अरसे बाद देखने को मिली। किसान आंदोलन के बाद पहली बार ऐसे संगठित प्रतिरोध का स्वर पहली बार सुनाई दिया। अभी इसको इसी रूप में देखने की जरुरत है, जब तक कि कोई दूसरी बात प्रमाणित नहीं हो जाती है।

भाई–बहन की जोड़ी मोदी–ताकाइची ने रचा इतिहास

नीरज

भारत और जापान ने अपने विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी संबंधों को नई मजबूती देते हुए नई दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया कि बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर उभर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करते हुए संबंधों को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को अपनी "छोटी बहन" बताते हुए भारत और जापान के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया, विशेषकर जापान के नारा प्रांत से भारत के ऐतिहासिक जुाव को रेखांकित किया। वहीं ताकाइची ने भी मोदी को अपना "बड़े भाई" बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग रहा। दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त वक्तव्य जारी किया और भारतीय तथा जापानी संस्थानों के बीच कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की सूक्ष्म तकनीकी क्षमता और भारत की साफ्टवेयर विशेषज्ञता का मेल वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को नई दिशा देगा। यह सहयोग केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत और जापान ने अपने पहले संयुक्त रक्षा विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली "यूनिकॉर्न" के सह विकास से संबंधित है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि दोनों देश क्वॉड समूह के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक बदलते सामरिक समीकरणों के बीच यह रक्षा सहयोग विशेष महत्व रखता है। साथ ही भारत और जापान ने ऊर्जा सुरक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, धातु और उर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की, जिसके तहत रुपये और येन में सीधे व्यापार की संभावना पर काम होगा। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अधिक रणनीतिक स्वायत्तता मिलेगी। साथ ही जापान ने अगले दस वर्षों में भारत में दस ट्रिलियन येन निवेश करने की घोषणा दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। वर्तमान में जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल परियोजना सहित कई आधारभूत ढांचा योजनाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जापान की प्रधानमंत्री के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस बात का स्पष्ट संकेत था कि टोक्यो भारत में निवेश बढ़ाने जा रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति मिली है। औषधि, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों के माध्यम से दोनों देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की व्यापक उत्पादन क्षमता और जापान की गुणवत्ता आधारित तकनीक मिलकर विश्व को सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं। इसके साथ ही भारत जापान जैव गैस पहल के अंतर्गत भारत में एक हजार जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देखा जाये तो यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है। चीन की सैन्य सक्रियता, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने भारत और जापान को और करीब ला दिया है। अमेरिका की विश्वसनीयता

को लेकर उठते सवालों के बीच टोक्यो अब नई दिल्ली को अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों में देख रहा है। भारत भी जापान को केवल निवेशक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामरिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंधों ने भी इस साझेदारी को मजबूती दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी की जापान यात्राओं से शुरू हुआ यह संबंध अब व्यापक सामरिक साझेदारी का रूप ले चुका है। वर्तमान वार्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत जापान संबंध एशिया की सबसे निर्णायक रणनीतिक धुरी बन सकते हैं। देखा जाये तो भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती का प्रभाव केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन पर दिखाई देगा। लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सहयोग और सामरिक विश्वास पर आधारित यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, वैश्विक आपूर्ति संकट और बदलती भू–राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और जापान का साथ आना एशिया में एक नए रणनीतिक संतुलन का संकेत माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी न केवल व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक भरोसेमंद और स्थिर शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकती है।

दिल्ली मेट्रो का यह फैसला- बढ़ जाएगी यात्रियों की परेशानी

संतोष

दुनिया भर के विकसित देशों के विकास की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। बेहतर सड़क और शानदार सार्वजनिक परिवहन (बस, मेट्रो, ट्रेन आदि) व्यवस्था। कई मायनों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर सरकार द्वारा किए गए खर्च को बड़ा निवेश ही माना जाता है क्योंकि दशकों तक इसका फायदा उस देश की अर्थव्यवस्था को मिलता रहता है। भारत जैसे देश के लिए बेहतर, सुगम और तेज रफ्तार वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो और भी जरूरी है क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और गैस के आयात पर ही खर्च होता है। तमाम दावों के बीच कड़वी सच्चाई तो यही है कि भारत पेट्रोल–डीजल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और हमारी निर्भरता किस हद तक है, इसका अंदाजा ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई के असर के रूप में हम सबको दिख ही गया है। भारत के लगभग हर शहर में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है लेकिन सार्वजनिक परिवहन की लचर व्यवस्था के कारण लोग उससे भी ज्यादा तेजी से पर्सनल गाड़ियां खरीदते हैं और नतीजा हर तरफ ट्रैफिक जाम यानी पेट्रोल–डीजल और गैस की बर्बादी। दिल्ली में भी मेट्रो का तेजी से विस्तार तो हो रहा है लेकिन यह दिल्ली की जरूरतों के लिहाज से अभी भी काफी पीछे है। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नकारते हुए दिल्ली मेट्रो में इसकी शुरुआत के समय ही यह फैसला किया गया था कि स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और पत्रकार सहित किसी भी कैटेगरी में किसी को भी रियायती दरों पर कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। थोड़े बहुत विरोध के बाद सबने इसे स्वीकार कर लिया जबकि दिल्ली की सरकारी परिवहन व्यवस्था यानी डीटीसी बसों में कई कैटेगरी के यात्रियों को रियायती दरों पर पास आज भी जारी किए जाते हैं। लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला कर रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी शायद यह भूल गए हैं कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन यात्रियों के प्रति है जो उन्हें महंगा किराया देकर मेट्रो में सफर करते हैं। ये अधिकारी, यह भी भूल जाते हैं कि ये भारत है, जहां नैतिकता से जुड़े मुद्दों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिल्ली मेट्रो ने अब यह फैसला किया है कि वो यात्रियों को अब विज्ञापन सिर्फ दिखाएगा ही नहीं बल्कि सुनाएगा भी। यानी जब आप मेट्रो के अंदर सफर करते समय, यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है ताकि आप अपने स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर सकें तो इस बीच आपको दिल्ली मेट्रो अलग–अलग कंपनियों के विज्ञापन सुनने को मजबूर कर देगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी क्डत्ब् ने अपने नॉन–ऑपरेशन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ट्रेन के अंदर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने यह दावा भी किया है कि कंपनियों के ऑडियो विज्ञापन से मेट्रो के अंदर होने वाली जरूरी घोषणाओं जैसे– श्अगला स्टेशन कौन सा है, दरवाजे बंद होने वाले हैं, दरवाजों से हटकर खड़े रहें, यह ट्रेन कहां तक जाएगीश पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। आपको बता दें कि, वर्तमान में भी दिल्ली मेट्रो की कमाई का सबसे बड़ा जरिया मेट्रो ऑपरेशन यानी इसपर सफर करने वाले यात्रियों से ही आता है। जबकि अन्य कामों यानी गैर ऑपरेशनल गतिविधियों से कुल कमाई का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही आता है जिसमें हर तरह के विज्ञापन (स्टेशनों के नाम तक बेचना शामिल है) शामिल हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टेशनों पर दुकानों, कियोस्क, एटीएम और पार्किंग से भी कमाई होती है। जब यात्री खचाखच भरे मेट्रो में (अगला स्टेशन जानने के लिए) डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं देख पाता है, तब मेट्रो हमें विज्ञापन सुनाना चाहता है। लेकिन यह शायद पहला मामला नहीं है जब दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने ऐसा फैसला किया हो। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसलों की तो एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक सिंपल सा स्मार्ट कार्ड जारी किया गया था, जिसे यात्री बड़ी ही आसानी से किसी भी स्टेशन से बनवा सकता था और खराब होने पर लौटा भी सकता था। अब मेट्रो ने बैंक से जुड़े कार्ड को थोपने के लिए साधारण वाला स्मार्ट कार्ड छापना ही बंद कर दिया है। प्लास्टिक वाला पुराना टोकन बंद करके, कागज वाला देने लगे हैं जिससे हर स्टेशन के कस्टमर केयर पर आपको कागजों का ढ़ेर नजर आएगा। मेट्रो ने नहीं ले जाने वाले सामानों की लंबी–चौड़ी लिस्ट जारी कर रखी है लेकिन उन्हें स्टेशनों पर चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में कोई खतरा नजर नहीं आता। हद तो तब हो जाती है जब ये अपने स्टेशनों पर बड़े–बड़े होर्डिंग लगाकर कंडोम का भी विज्ञापन करते नजर आते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को यह बताया जाए कि इसके गठन का मूल उद्देश्य पूरी दिल्ली को जोड़ना था एवं है(अब तो इसमें छब्ब् का इलाका भी शामिल हो गया है) और यात्रियों को तेज और सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था देना है। अभी भी दिल्ली एनसीआर का काफी बड़ा इलाका मेट्रो की सुविधा से वंचित है। जिसमें से कई रूट तो दिल्ली मेट्रो के लिए काफी प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प, विश्व कप और राजनीति का खेल

राजेश

अमेरिका–ईरान तनातनी की जड़ में तेल संसाधनों पर कब्जा और मिडिल ईस्ट पर प्रभुत्व कायम रखने के साम्राज्यवादी इरादे भी काम करते हैं। 1900 के दशक से एंग्लो–ईरानियन तेल कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम रखा था। 1953 में मोहम्मद मोसादेह के प्रधानमंत्री बनने के बाद ईरान में ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध तेज हो गया। मेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम हो चुका है लेकिन विश्व कप फुटबॉल पर उसकी लंबी और गहरी छाया साफ दिखाई पड़ती है। मौजूदा विश्व कप कई मायनों में अलग है। यह पहला विश्व कप है जिसकी मेजबानी तीन देश–अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। 48 टीमें 104 मैचों में हिस्सा ले रही हैं। कनाडा, मेक्सिको के हिस्से में 13–13 मैच आए हैं और बाकी 78 मैचों का मेजबान अमेरिका है। टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एमबापे, नार्वे के एर्लिंग हालैंड जैसे चमकते सितारों ने अपना दबदबा दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मैदान से बाहर अलग तरीके से अपनी ताकत दिखा रहे हैं।ट्रम्प ने ईरान से आए अतिथियों के लिए शिष्टाचार और कूटनीति के तौर–तरीकों को ताक पर रख दिया है। वे टूर्नामेंट के दौरान भी अपने इमिग्रेशन एजेंडा को जोर–शोर से लागू कर रहे हैं। राष्ट्रपति यह सब उस देश में कर रहे हैं जहां पूरी दुनिया से आकर लोग बसे हैं। शायद अमेरिका ही ऐसा एकमात्र देश है जहां इतनी ज्यादा नस्लों, धर्मों और

संस्कृतियों के लोग मिलेंगे। वहां किसी कोने में यूरोप तो कहीं एशिया तो कहीं अफ्रीका महाद्वीप सहित दुनिया के सभी देशों के लोग मिल जाएंगे। अमेरिका को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने में उसकी बहुलता की निर्णायक भूमिका है। ट्रम्प इस पर पानी फेरने की कोशिश में जुटे हैं।11 जून को पहले मैच की व्हिसल बजने से पहले ही विवादों की शुरुआत हो गई थी। कई टीमों के खिलाड़ियों और दर्शकों को कस्टम्स, इमिग्रेशन (आईसीई) की कड़ी सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन (फीफा) द्वारा चुने गए सोमालिया के रैफरी उमर ओर्टन को मियामी कस्टम्स ने रोका और वापस भेज दिया। 2025 में ओर्टन को अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ रैफरी का दर्जा मिला है। अमेरिकी अधिकारियों ने ओर्टन को प्रवेश न देने का अस्पष्ट कारण बताया कि अवांछनीय लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस अपमान की अफ्रीका में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इसके अलावा सेनेगल, उजबेकिस्तान के खिलाड़यों को अकारण जांच से गुजरना पड़ा है।सबसे अधिक परेशानियां ईरान की टीम के सामने आई थी। अमेरिका से उसका टकराव कदम–कदम पर नजर आया है। इसकी शुरुआत 2025 में हो गई थी। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वीजा नहीं देने के बाद दिसंबर में ड्रा की घोषणा होने पर ईरान ने टूर्नामेंट के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। बाद में ईरान ने टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला लिया। उस वक्त अमेरिका–ईरान युद्ध शुरू नहीं हुआ था। वैसे, दोनों देशों के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास है। कई कारणों से ईरान में अमेरिका विरोधी भावनाओं का जोर रहा है। अमेरिका–ईरान तनातनी की जड़ में तेल संसाधनों पर कब्जा और मिडिल ईस्ट पर प्रभुत्व कायम रखने के साम्राज्यवादी इरादे भी काम करते हैं। 1900 के दशक से एंग्लो–ईरानियन तेल कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम रखा था। 1953 में मोहम्मद मोसादेह के प्रधानमंत्री बनने के बाद ईरान में ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध तेज हो गया। मोसादेह ने तेल क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे मिडिल ईस्ट के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर अमेरिका और ब्रिटेन को जबर्दस्त धक्का लगा। 1957 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीईए ने मोसादेह का तख्ता पलट दिया। सीआईए की मदद से शाह रजा पहलवी ईरान के शाह बन गए। राजशाही के खिलाफ 1978–79 में भीषण क्रांति की शुरुआत हो गई। लाखों लोग शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। शाह को ईरान से भागकर अमेरिका में शरण लेना पड़ी थी। 1979 में धार्मिक नेता अयातुल्ला खोमैनी की अगुआई में नई सरकार बनी। कई मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच संवाद का सिलसिला चलता रहा है। इस बीच ईरान ने परमाणु तकनीक हासिल कर ली। वह एटम बम बनाने की स्थिति में पहुंच गया है। लंबी बातचीत के बाद 2013 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय ईरान के परमाणु कार्यक्रम की गति धीमी करने के वास्ते एक समझौते पर दस्तखत हुए। हालांकि, ट्रम्प ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल में करार को एकतरफा तौर पर रद्द कर दिया। राष्ट्रपति जार्ज बुश ने तो ईरान को आतंकवाद की धुरी घोषित कर रखा था। ट्रम्प के शासनकाल में दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ी है। 2025 में ओमान में अमेरिका–ईरान शांति वार्ता के बीच इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। इस तनाव का खामियाजा ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका–ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद उम्मीद बढ़ी थी कि ईरानी टीम का रास्ता आसान होगा। लेकिन, ऐसा नहीं हो सका है। न्यूजीलैंड से 2–2 की बराबरी के बाद ईरानी टीम को उनके कार्यक्रम में बदलाव की सूचना मिली। उन्हें लॉस एंजिल्स में रात गुजारने की बजाय अमेरिका की सीमा के पास मेक्सिको के तिजुआना स्थित अपने ट्रेनिंग कैम्प में लौटने के लिए कहा गया। मैच रात 8 बजे खत्म हुआ था। मेक्सिको के लिए उनकी फ्लाइट रात 11 बजे थी। टीम के हेड कोच आमिर गेनलेनोएल की गुस्से से भरी प्रतिक्रिया आई कि समूचे वर्ल्ड कप में हमारी टीम सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित रही है। विश्व कप से बाहर होने के बाद ईरानी टीम के मैनेजमेंट ने उनके साथ हुए व्यवहार पर निराशा जताई है। यों भी टूर्नामेंट में ईरान की हिस्सेदारी को लेकर देश में विभाजन की स्थिति है। अमेरिका से टकराव को देखते हुए ईरान में बहुत लोग नहीं चाहते थे कि टीम विश्व कप में भाग ले। इसकी तस्वीर ईरान के मैचों में देखने मिली है। लॉस एंजिल्स में लगभग एक लाख ईरानी रहते हैं। वहां मैच के दौरान कुछ ईरानी दर्शक टीम के समर्थन में बैनर लहरा रहे थे तो कुछ लोगों ने ईरान में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की मांग करने वाले सैकड़ों लोगों की हत्याओं पर वर्तमान सरकार का विरोध किया है। ऐसे लोग टीम को दमनकारी शासन का प्रतिनिधि मानते हैं।

संक्षिप्त खबरें

रहीमाबाद में फायरिंग और मारपीट के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। रहीमाबाद थाना क्षेत्र में गाली–गलौज, लाठी–डंडों से मारपीट और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 32 बोर का कारतूस का खोखा, एक होल्स्टर, एक सैमसंग जेड फोल्ड–07 मोबाइल फोन तथा एक बलेनो और एक महिंद्रा थार वाहन भी बरामद किए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई 2026 को पीड़िता द्वारा थाना रहीमाबाद में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि विपक्षी पक्ष ने उसके और उसके परिवार के साथ गाली–गलौज की, लाठी–डंडों से मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। शिकायत के आधार पर थाना रहीमाबाद में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रारंभिक मुकदमे में अनिल, हरगोविंद, बबलू तथा 15 से 20 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था।विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल के निरीक्षण, वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। जांच में कुलदीप कुमार, राम सिंह और मनीष की संलिप्तता भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें 2 जुलाई की रात करीब 2रू10 बजे गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए। इनमें 32 बोर का एक कारतूस का खोखा, एक होल्स्टर, सैमसंग जेड फोल्ड–07 मोबाइल फोन, बलेनो कार (संख्या यूपी–32–क्यूबी–6446) तथा काले रंग की महिंद्रा थार (संख्या यूपी–32–पीपी–4141) शामिल हैं।

6,974 लोगों की जांच, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते मिले 1,316 लोगों का चालान

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए लखनऊ पुलिस ने दो दिनों तक देर रात विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में 256 स्थानों पर कुल 6,974 लोगों की जांच की गई, जिनमें 1,316 लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते हुए पाए गए। सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए चालान किया गया तथा भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।यह विशेष अभियान पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार के पर्यवेक्षण तथा सभी जोनों के पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में 30 जून और 1 जुलाई की रात 10 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक चलाया गया। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वालों, राहगीरों और विशेषकर महिलाओं को असुविधा पहुंचाने वाले लोगों तथा बाजारों और सड़कों पर अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना था।अभियान के तहत सभी जोनों के सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों ने अपनी–अपनी पुलिस टीमों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों, पार्कों, बस अड्डों, चौराहों, सड़कों और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक जांच अभियान चलाया।

सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने पकड़ा फाइबर केबल चोर गिरोह

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से करीब 612 फीट लंबी, लगभग तीन कुंतल वजनी ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक वायर कटर तथा एक एक्सयूवी–500 कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की गई केबल को औने–पौने दामों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे।यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अभियान का पर्यवेक्षण पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) अमित कुमार आनंद, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव ने किया। अतिरिक्त निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई को सूचना मिली थी कि कृष्णागांव के सामने आउटर रिंग रोड नहर के पास एक कार में दो युवक चोरी की गई ऑप्टिकल फाइबर केबल के बंडल लेकर खड़े हैं और राहगीरों से उसे बेचने की बातचीत कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मारूफ (24) निवासी बाबागंज, थाना रूपडीह, जनपद बहराइच, हाल निवासी कांशीराम कॉलोनी, लौलेही, चिनहट तथा शानू (24) निवासी नंदपुर डूडा कॉलोनी, थाना चिनहट के रूप में हुई है।

सआदत अली खां मकबरे की फसाड लाइट चोरी का खुलासा

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के ऐतिहासिक सआदत अली खां मकबरे से फसाड लाइटें चोरी करने के मामले में कैसरबाग पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर फिलिप्स कंपनी की पांच चोरी की गई फसाड लाइटें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में आरोपी के दो साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे आरोपी की काफी समय से तलाश की जा रही थी।पुलिस के मुताबिक, 16 मई 2026 को रिजवान हुसैन ने कैसरबाग थाने में तहरीर देकर बताया था कि सआदत अली खां मकबरा परिसर में लगी फसाड लाइटें अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक चंदन कुमार मिश्रा कर रहे थे।जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल वांछित आरोपी स्वास्थ्य भवन चौराहे के पास स्थित ग्लोब पार्क में घूम रहा है और किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही कैसरबाग पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अंशू कश्यप (19 वर्ष) निवासी बलवरिया कुतुबपुर, मनकामेश्वर मंदिर के पीछे, थाना हसनगंज बताया।पूछताछ के दौरान अंशू कश्यप ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों अल्तमश और सोहेल के साथ मिलकर मकबरे से फसाड लाइटें चोरी की थीं।

जौनपुर में टीईटी का अंतिम दिन, 9584 अभ्यर्थी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। तीन दिवसीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) गुरुवार, 2 जुलाई से शुरू हुई। परीक्षा का अंतिम दिन शुक्रवार, 4 जुलाई को था, जिसमें 9584 अभ्यर्थी शामिल हुए। यह परीक्षा जिले के कुल 23 केंद्रों पर आयोजित की गई। इस तीन दिवसीय परीक्षा में कुल 56,882 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। नकल रोकने और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। इसमें जूते–मोजे उतरवाए गए और शर्ट की बाहें व कॉलर खोलकर जांच की गई। पानी की बोतल ले जाने से पहले उसके रैपर को भी हटाकर जांच की गई। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत योजना तैयार की थी। परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दो–दो पालियों में आयोजित की गई, जबकि 4 जुलाई को केवल एक पाली थी। पहली पाली सुबह 9रू30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 2रू30 बजे से शुरू हुई। जिलाधिकारी ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। परीक्षा के सुचारु एवं निष्पक्ष संचालन के लिए 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 23 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 5 आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट और 8 आरक्षित स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। जिलाधिकारी ने केंद्र अधीक्षकों को उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर आयोग द्वारा निर्धारित सभी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा की गोपनीयता, पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के साथ–साथ अभ्यर्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना केंद्र अधीक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लक्खीशाह बंजारा सामाजिक समरसता, राष्ट्रसेवा के प्रतीक - राकेश मौर्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने बाबा लक्खीशाह बंजारा की जयंती जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य की अध्यक्षता में शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाई। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा लक्खीशाह बंजारा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन, संघर्ष, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र सेवा में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा लक्खीशाह बंजारा ने अपने साहस, त्याग और समाज सेवा के बल पर इतिहास में गहरी छाप छोड़ी है। उनका जीवन हमें सामाजिक न्याय, भाईचारे, समानता और मानवता की सेवा के लिए सदैव प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी उनके आदर्शों को जन–जन तक पहुंचाने तथा सामाजिक सद्भाव और पिछड़े, वंचित एवं शोषित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत है। कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भी जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने की। इसमें संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी को सशक्त बनाने, सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम तथा जनता की समस्याओं को लेकर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही आगामी संगठनात्मक रूपरेखा भी तैयार की गई। राकेश मौर्य ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की नीतियों एवं पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की विचारधारा को घर–घर तक पहुंचाएं। उन्होंने जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए समाजवादी पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पीडीए वृक्षारोपण कार्यक्रम को भव्य स्तर पर आयोजित किया जाए। बैठक का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वीआईपी दर्शन कराने में टिन्नू गैंग का लाखों का खेल, मंदिर के कर्मियों के अलावा बाहरी लोग भी शामिल

लखनऊ, (संवाददाता)। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू एक गैंग बनाकर वीआईपी दर्शन करवाने के खेल में हर महीने लाखों रुपये की वसूली करता था। जेल गए आरोपी उसके गैंग के साथी थे। रोजाना रकम का बंटवारा होता था। यह खेल प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अधिक बढ़ गया था। एसआईटी जांच में इसका खुलासा हुआ है। इसमें मंदिर के कई और कर्मचारी व कुछ बाहरी लोगों पर शिकंजा कस सकता है। दरअसल, राम मंदिर में दर्शन की कई व्यवस्थाएं हैं। सामान्य श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर दर्शन करते हैं। इसमें काफी वक्त लगता है। वहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल से आए श्रद्धालुओं को चंद मिनट में दर्शन हो जाते हैं। इसके लिए वीआईपी पास ट्रस्ट की ओर से जारी किए जाते हैं, जो निशुल्क हैं। लेकिन इसी में यह पूरा खेल होता था। श्रद्धालुओं

को आसानी से भव्य दर्शन करवाने की बात बताकर उनसे रुपये वसूले जाते थे। जेल भेजे गए आरोपियों ने अयोध्या के दर्जनों होटल, होम स्टे और धर्मशालाओं में संपर्क कर रखा था। वहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं से होटल या होम स्टे मालिक वीआईपी दर्शन करवाने की बात करते थे। प्रति श्रद्धालु 500 से 1000 रुपये तक आमतौर पर वसूले जाते थे। जब देखते थे कि कोई श्रद्धालु आर्थिक रूप से अधिक मजबूत है, तो उससे दो–दो हजार या उससे भी अधिक रकम लेते थे। उसके बाद ये सभी टिन्नू एंड कंपनी से संपर्क कर श्रद्धालुओं की डिटेल साझा करते थे। ये सभी उनके वीआईपी पास बनवाकर दर्शन करवाते थे। होटल आदि के जरिये श्रद्धालुओं को लाने की जिम्मेदारी अनुकल्प, करुणेश, मनीष, अविनाश और लवकुश आदि की रहती थी। फिर टिन्नू पास बनाता था। क्योंकि टिन्नू को पास बनाने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन वह चंपत, अनिल मिश्र और गोपाल राव की आईडी का इस्तेमाल कर पास बना देता था। इन छह के अलावा कई और वहां के कर्मी इस पूरे खेल में शामिल हैं। मंदिर के वीआईपी रूट व गेट के पास एक नाम सबसे अधिक चर्चा में रहता है, वह है छोटू का। वहां यह कहा जाता है कि जिस किसी को वीआईपी दर्शन करने हों, वह छोटू से संपर्क करे, तत्काल हो जाएगा। क्योंकि छोटू ने भी टिन्नू व अन्य कई लोगों से संपर्क बना रखा है। रकम लेकर दर्शन करवाता है और फिर रकम का बंटवारा होता है।

जौनपुर पुलिस ने 151 गुमशुदा मोबाइल किए बरामद, 32 लाख रुपये के फोन मालिकों को लौटाए

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शनिवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 151 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई गई है। इस मामले शनिवार को सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने खुलासा करते हुए बताया कि जौनपुर पुलिस अब तक 1,791 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 3.60 करोड़ रुपये है। यह अभियान लगातार साइबर क्राइम थाना द्वारा संचालित किया जा रहा है। बरामद किए गए 151 मोबाइल फोन जौनपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, वाराणसी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़ और भदोही समेत कई जिलों से प्राप्त हुए। वहीं, कुछ मोबाइल दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों से भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सीईआईआर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई। बरामद मोबाइलों में वनप्लस, वीवो, रेडमी, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, पोको, नोकिया और सैमसंग सहित विभिन्न कंपनियों के हैंडसेट शामिल हैं। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताते हुए जौनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने आमजन से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल उसकी शिकायत दर्ज कराएं और पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे मोबाइल की शीघ्र बरामदगी संभव हो सके। उन्होंने साइबर अपराधों से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी या अन्य साइबर अपराध ा का शिकार होता है, तो तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत करें। साथ ही नजदीकी थाने की साइबर हेल्पडेस्क पर भी संपर्क किया जा सकता है।

एनसीएलटी में अंसल मामले की सुनवाई

लखनऊ, (संवाददाता)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप की सुनवाई राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में शुक्रवार को होगी। मामले से करीब पांच हजार आवंटियों का हित जुड़ा है। बीती 17 दिसंबर को राष्ट्रीय कंपनी विधि ा अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में सुनवाई पूरी हुई थी और फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था, जिसे सात जनवरी को जारी किया गया। इसमें आवंटियों को यह राहत दी गई कि वह अपना पक्ष एनसीएलटी के सामने रख सकेंगे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पखवाड़े जुटे भाजपाई

लखनऊ, (संवाददाता)। भाजपा महानगर की ओर से बृहस्पतिवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पखवाड़ा के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन विधानसभा मार्ग स्थित सहकारिता भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंह और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी

का जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान, राष्ट्रीय एकता और मजबूत भारत के निर्माण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे डॉ. मुखर्जी के विचारों को आत्मसात कर समाज के हर वर्ग तक पहुंचें और संगठन को सशक्त बनाएं।

जौनपुर जिला अस्पताल की लिफ्ट एक महीने से बंद, बुजुर्ग-दिव्यांग व गंभीर मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय में पिछले लगभग एक महीने से लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को हो रही है, जिन्हें अस्पताल की पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, लिफ्ट का संचालन लो वोल्टेज और तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित हुआ है। हालांकि, मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण सुविधा लंबे समय से बंद रहने के बावजूद इसे जल्द बहाल करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। जिला अस्पताल की पहली और दूसरी मंजिल पर ओपीडी, वार्ड और अन्य जरूरी विभाग संचालित होते हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। वर्ष 1998 में निर्मित इस अस्पताल में गंभीर मरीजों को वार्ड और ऑपरेशन थिएटर तक आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से लिफ्ट लगाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इसके बंद होने से यह सुविधा पूरी तरह ठप पड़ी है। लिफ्ट बंद होने के कारण कई बार तीमारदारों को मरीजों को गोद में या कंधे पर उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ रहा है। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 900 से 1200 मरीज पहुंचते हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन से लिफ्ट को तत्काल चालू कराने की मांग की है, ताकि गंभीर मरीजों को राहत मिल सके और इलाज में किसी प्रकार की देरी न हो।इस संबंध में शनिवार को जानकारी ।

सातवें वर्ष भी बिजली दरें स्थिर, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : ए.के. शर्मा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि लगातार सातवें वर्ष सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों को यथावत रखना प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीतियों का परिणाम बताया।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता, हरित ऊर्जा को बढ़ावा और आधुनिक विद्युत अवसंरचना के विकास की दिशा में जो पहल हुई है, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने प्रभावी ढंग

से लागू किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश बिजली उत्पादन, आपूर्ति, वितरण सुधार और उपभोक्ता सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।ए.के. शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए टैरिफ सब्सिडी बढ़ाकर 20,400 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 17,100 करोड़ रुपये थी। इससे लाइफलाइन उपभोक्ताओं, ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों, निजी नलकूप संचालकों और ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं को पहले की तरह राहत मिलती रहेगी।उन्होंने कहा कि यूपीईआरसी ने लगभग 2,580 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी गैप के बावजूद बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की। आयोग ने माना कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और राज्य के वितरण निगमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन तथा उपलब्ध रेगुलेटरी सरप्लस के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की आवश्यकता नहीं है। इसे उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन और सुधारों का सकारात्मक परिणाम बताया।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है। ग्रीन एनर्जी अतिरिक्त टैरिफ को पूर्ववत रखा गया है। साथ ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और बैटरी ऐज ए सर्विस (बीएएएस) प्रदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सौर ऊर्जा अवधि ा में ईवी चार्जिंग पर 20 प्रतिशत कम टैरिफ की व्यवस्था की गई है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड विद्युत मांग की सफल आपूर्ति, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का विस्तार, तकनीकी सुधार, लाइन हानियों में कमी तथा उपभोक्ता सेवाओं में पारदर्शिता के कारण उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। सरकार का लक्ष्य केवल निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि बिजली को आम उपभोक्ता की पहुंच में बनाए रखना भी है। इसी उद्देश्य से लगातार सात वर्षों से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

'कार्डधारकों को निर्धारित मानक के अनुरूप नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें–जिला पूर्ति अधिकारी'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित किया है कि माह जुलाई, 2026 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रथम त्रैमास (अप्रैल, मई व जून, 2026) के सापेक्ष चीनी का वितरण 06 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक वितरण ई–पॉस वेइंग मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। जनपद में अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को 14 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 21 कि0ग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रथम त्रैमास (अप्रैल, मई व जून, 2026) के सापेक्ष 03 कि0ग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रु0–18ध्–प्रति कि0ग्रा0 की दर से रु0–54ध्–(सशुल्क) में वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुबिधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से चीनी प्राप्त कर सकेंगे। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 कि0ग्रा0 गेहूँ व 03 कि0ग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि 20 जुलाई 2026 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। समस्त उचित दर विक्रेओं को निर्देशित किया जाता है कि वह नोडल अधिकारियोंध् पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की देखरेख में कार्डधारकों को निर्धारित मानक के अनुरूप नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें, उचित दर दुकान पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का बैनर लगा हो और प्रत्येक कार्डधारक को वितरण के समय प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के मात्रा की पर्ची उपलब्ध करायी जाय। वितरण का समय प्रातः काल 08.00 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 02.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा। वितरण के समय राशन कार्ड में दर्ज समस्त यूनिटों की ई–के0वाई0सी0 पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाए तथा वितरण अवधि में कार्डधारकों को अनुमन्य खाद्यन्न एवं चीनी के अतिरिक्त अन्य अधोमानक वस्तुए (तेल, हल्दी, मिर्चा, नमक आदि) क्रय किये जाने हेतु कार्डधारकों को बाध्य न किया जाए। इस का कड़ाई से अनुपालन सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारीध्पूर्ति निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध मे यदि शिकायत पायी जाती है तो विक्रेता के साथ–साथ सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है। समस्त उचित दर विक्रेता इस आशय की सूचना अपनी उचित दर दुकान पर चस्पा करेंगे। खाद्यान्न वितरण कराए जाने के साथ–साथ अन्त्योदय एवंआ अनुमन्य पात्र गृहस्थी के समस्त सदस्यों सहित आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु सम्बन्धित को प्रेरित करेंगे। वितरण अवधि में समस्त पूर्ति निरीक्षक व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी भ्रमणशील रहते हुए नियमानुसार कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करायेंगे साथ अपने–अपने क्षेत्र में उचित दर दुकानों से सम्बद्ध अन्त्योदय लाभार्थियों का रैण्डम आधार पर चीनी प्राप्ति तथा मूल्य के सम्बन्ध में जॉच करना सुनिश्चित करेंगे। वितरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत विभागीय टोल फ्री नम्बर, 1800–1800–150 एवं 1967 पर शिकायत की जा सकती है। कार्डधारको से अपील की जाती है कि सर्वर, इन्टरनेट आदि तकनीकी समस्या के दृष्टिगत अपना धैर्य बनाये रखेंगे व वितरण में यथोचित सहयोग प्रदान करेंगे।

जनता दर्शन में आई शिकायतों का डीएम के निर्देश पर हो रहा त्वरित निस्तारण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।जिलाधिकारी के जनता दर्शन के दौरान आवेदक रोहित दास निवासी कुशमाहा तहसील सदर अयोध्या ने विपक्षी द्वारा तालाब की भूमि को अवैध कब्जा किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने अपर नगर आयुक्तध्एसडीएम सदर को जांच हेतु निर्देशित किया था। तत्क्रम में अपर नगर आयुक्त ध्एसडीएम सदर ने तत्कालीन नायब तहसीलदार नगर निगम के प्रर्वतन दल तथा पुलिस बल की उपस्थिति में तालाब की भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त करवा दिया गया है।इसी कड़ी में आवेदक राजित राम यादव एडवोकेट निवासी हासापुर अयोध्या ने विद्युत तार हटवाये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को विद्युत तार हटवाये जाने का निर्देश दिया था। तत्क्रम में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत ने निरीक्षण में विभागीय स्तर पर कोई नवीन त्रुटि अथवा उत्तरदायित्व परिलक्षित नही हुआ। वर्तमान स्थिति भवन निर्माण में किये गये परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई। शिकायतकर्ता की सहमति से उक्त न्यूट्रल तार को सही कराने की कार्यवाही को पूर्ण करा दिया गया है।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया हैं कि जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों को लंबित रखना अथवा लापरवाही बरतना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिकायतकर्ता को खड़ा ना रखा जाए,सम्मानपूर्वक बैठा कर उनकी शिकायतें सुनीं जाए।उन्होंने ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन को त्वरित राहत मिले और उन्हें अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े।

मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस मे भिड़े

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।नगर कोतवाली क्षेत्र में गुलाबबाड़ी के सामने गुरुवार की शाम मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया।विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई।जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की खबर पर पहुंची पुलिस ने विवाद में शामिल लोगों को हिरासत में लिया है। शुक्रवार को इनमें से चार का पुलिस ने शांति भंग में चालान किया है।कोतवाली पुलिस का कहना है कि गुलाबबाड़ी के सामने चाय की दुकान है। जिसपर कुछ लड़के चाय पीने आए थे।बैठने के बेंच को लेकर आपस में विवाद हुआ जो मारपीट में बदल गई। इसमें अन्य लोग भी शामिल हो गए। पुलिस ने विवाद में शामिल 19 वर्षीय मो आदिल पुत्र इश्तियाक,इसके भाई 35 वर्ष मो आबिद निवासीगण खवासपुरा,20 वर्षीय सादिक पुत्र मो मतीन निवासी पुरानी सब्जी मंडी फतेहगंज और 25 वर्षीय गुफरान अहमद निवासी बहेलिया टोला देवकाली को पाबंद करते हुए जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवा सभी का शांति भंग में चालान किया है।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओ को किया जागरूक

अयोध्या।शनिवार को मिशन शक्ति अभियान फेज–5 के तहत महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला उप निरीक्षक प्रिया व अन्य पुलिस कर्मियों ने जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुरुष चिकित्सालय, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर मिशन

शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक किया है।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।इस मौके पर पीआरडी किरन सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रही।

गोशाईगंज स्टेशन पर लगा सीसीटीवी कैमरा अगले महीने से हों जायेगा क्रिया शील, अपराधों मे आएगी कमी

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।लखनऊ–अयोध्या कैट– वाराणसी रेल खंड स्थित गोशाईगंज स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यदाई संस्था द्वारा प्रवेश द्वार,टिकट काउंटर पर 1–1, प्लेट फॉर्म नं0–2 पर दो कैमरो के साथ फुट ओवर ब्रिज एवं पीएफ नं0–1 पर 3–3(कुल 10) कैमरे लगा दिये गये हैं।जो अगले महीने तक क्रियाशील हो जायेंगे।परिसर में लगे इन सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग अकबरपुर जंक्शन पर तैनात आरपीएफ टीम करेगी।कैमरो के क्रियाशील होते ही छिट–पुट घटनाओं में जहां कमी आएगी वही इसी के सहारे आरपीएफ भी छोटे–बड़े घटनाओं को बड़े आसानी से पर्दाफास कर लेगी!स्टेशन परिसर मे लगाए गए सीसीटीवी कैमरो की पुष्टि रेल कर्मियों ने भी की हैं!मालूम हो कि गोशाईगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी एवं पश्चिमी रेल बैरियर सं0– 93 ध्94 के साथ–साथ स्टेट हाईवे के आजमगढ़–अयोध्या धाम स्थित रेल बैरियर सं0– 96 के अतिरिक्त स्टेशन के इन महत्वपूर्ण स्थानो पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने की मांग बीते 2 माह पूर्व गोशाईगंज नगर पंचायत की सभासद एवं जय बाबा अमर नाथ बर्फानी सेवा समिति (रजि0) की अध्यक्ष आरती जयसवाल ने उरे0 लखनऊ के डीआरएम,सी0 डीसीएम सहित अन्य अधिकारियो को पत्र भेजकर की थीं!सूत्र बताते है कि दूसरे चरण में इन सभी रेल बैरियरों पर भी कैमरे लग जायेंगे।सभासद आरती जयसवाल ने बताया कि सर्कुलटिंग एरिया मे लगे हाईमास्ट एवं प्लेटफार्म परिसर के अंदरध्बाहर बिगड़े पड़े बल्बो को बदलने के साथ ही पुरानी बिल्डिंग के पीछे एक 200

वाट की नई लाइट लगाने के अतिरिक्त पीएफ नं0–1 पर यात्रियों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए पुराने टीन सेड के नीचे 2 पंखे अतिरिक्त लगाए जाने का अनुरोध अयोध्या कैंट मे तैनात बिजली विभाग के जिम्मेदारों से किया गया थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है।उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक यह सभी मांगे भी पूर्ण हो जाएंगी।

अग्रवाल महिला सभा की नयी अध्यक्षा चुनी गई पूनम अग्रवाल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।अग्रवाल महिला सभा की बैठक सिविल लाइन स्थित होटल कृष्णा पैलेस में हुईं जिसमें 2 साल के लिये सर्वसहमति से पूनम अग्रवाल को 2 साल के लिये नयी अध्यक्षा चुनी गई।चुनाव अधिकारी पूर्व संरक्षक उषा अग्रवाल और बीना अग्रवाल रहीं जिन्होंने पूनम अग्रवाल को अध्यक्षा, महामंत्री दीप्ती अग्रवाल, और कोषाध्यक्षा क्षमा अग्रवाल को नियुक्त किया।पूर्व अध्यक्षा प्रीति बंसल ने वर्तमान अध्यक्षा पूनम अग्रवाल को बैच पहना कर सम्मानित किया।पूर्व महामंत्री सीमा अग्रवाल ने नयी महमंत्री दीप्ती अग्रवाल को पदभार सौंपा।पूनम अग्रवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य समाज की महिलाओं को समान अवसर देना है।हर घर की महिला को आगे लाना है। इस बैठक में संरक्षक विमला अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, नीलम अग्रवाल,शोभा अग्रवाल ,विजयलक्ष्मी अग्रवाल ,संगीता अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य डिंपल बंसल, रूबी बंसल ,स्मिता अग्रवाल ,मोनिका अग्रवाल ,दीपाली अग्रवाल, सौम्या अग्रवाल , छवि अग्रवाल,नेहा अग्रवाल कोमल अग्रवाल ,मीनू अग्रवालऔर सभी सदस्य उपस्थित रहे।सभी ने नए पदाधिकारियों को बधाई दी।इस बैठक में आगामी तीज के कार्यक्रम की भी चर्चा की गई और इस तीज को उत्साह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया।

फुटबॉल – वैलेंटाइन ने 5–2 से दर्ज की जीत

गोरखपुर, (संवाददाता)। वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब की ओर से रामगढ़ताल क्षेत्र में आयोजित अंडर–12 आयुवर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को चार मुकाबले खेले गए। पहले मैच में वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब ने 5–2 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब और चरगावां फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इसमें वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब ने 5–2 से जीत दर्ज की। दूसरा मैच फतेहपुर फुटबॉल क्लब और सनातन फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इसमें फतेहपुर की टीम ने 4–1 से जीत दर्ज की। तीसरा मैच संदीप स्पोर्टिंग पीपीगंज और चरगावां फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इसमें संदीप स्पोर्टिंग ने 3–0 से एकतरफा जीत दर्ज की। दिन का अंतिम मुकाबला एमपी इंटर कॉलेज और सनातन फुटबॉल है।

किक बॉक्सर सनी को मिला युवा प्रतिभा नेशनल टैलेंट सम्मान

गोरखपुर, (संवाददाता)। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के स्थापना दिवस पर आयोजित कृषि क्षेत्र में नवाचार और बैंकिंग कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए समाजशास्त्र के छात्र एवं अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सर सनी सिंह को युवा प्रतिभा नेशनल टैलेंट सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान पद्मश्री डॉ. रामचेत चौधरी और एसबीआई के डीजीएम सुमन बख्शी ने संयुक्त रूप से दिया। सनी सिंह ने हाल ही में 5वीं वाको इंडिया इंटरनेशनल किकबॉक्सिंग कप–2026 में इटली के खिलाड़ी को हराकर रजत पदक जीता। अगस्त में गुजरात में होने वाली सीनियर नेशनल किकबॉक्सिंग चौंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि सनी सिंह ने अनुशासन और समर्पण के बल पर खेल और शिक्षा दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एवं ऐश्रा ग्रुप के चेयरमैन अतुल सराफ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करना बड़ी उपलब्धि है।

पीपीएस से आईपीएस बने एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी

अयोध्या।जिले में तैनात एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी की पदोन्नति आईपीएस पद पर हो गई है।शुक्रवार को डीजीपी राजीव कृष्ण ने उनके कंधे पर आईपीएस का प्रतीक चिन्ह लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। उनके आईपीएस बनने पर जिले के एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी,सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी, सीओ सदर अरविंद सोनकर, सीओ

मिल्कीपुर पीयूष,सीओ रुदौली आशीष निगम, सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी,सीओ बीकापुर सहित सभी थानों के निरीक्षक व महिला थानाध्यक्ष ने उनको आईपीएस पद पर पदोन्नति होने पर बधाई दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनपद में सभी पुलिसकर्मियों से अच्छा सहयोग मिला हुआ है और आगे भी मिलता रहेगा और इसी तरह जानता से भी मिल रहा है।

राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई

प्रयागराज, (संवाददाता)। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव, विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष चाहे जो भी रणनीति अपना ले, प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ष्अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में चोरी की घटना और जांच के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जिन लोगों ने परम तपस्वियों की तरह काम किया है,।

अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज से निकाले गए 16 शिक्षकों को राहत

वाराणसी, (संवाददाता)। अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज से पिछले साल जून महीने में निकाले गए 16 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। मामले में काशी विद्यापीठ के कुलपति ने सुनवाई करते हुए 30 जून 2026 को एक

आदेश जारी कर कॉलेज प्रबंधन से सभी शिक्षकों की सेवा बहाल करते हुए नियमानुसार वेतन, अन्य देयकों का भुगतान करने को कहा है। हालांकि, कुलपति के इस फैसले के बावत कॉलेज के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में अंतिम फैसला प्रबंध समिति की बैठक में होगा। अग्रसेन पीजी कॉलेज प्रबंधन की ओर से जून 2025 में 16 शिक्षकों को निकाला गया था। इसके पीछे वजह शिक्षकों का अनुमोदन न होना, कम उपस्थिति आदि का हवाला दिया गया था। इसके बाद से ही न्याय के लिए शिक्षक कॉलेज से लेकर विवि तक का चक्कर लगा रहे थे। शिक्षकों ने 30 अगस्त 2025 को काशी दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भी कॉलेज में सेवा बहाली की गुहार लगाई थी। मामले में कोर्ट का भी सहारा लिया था। कोर्ट ने एक आदेश में काशी विद्यापीठ के कुलपति को मामले में सुनवाई करने की बात कही थी। इस पर कुलपति ने सुनवाई की और 30 जून 2026 को इसका आदेश जारी किया। प्राचार्य प्रो. मिथिलेश सिंह ने पूछे जाने पर बताया कि आदेश की जानकारी उनको हैं लेकिन कॉलेज से जुड़े किसी भी फैसले में कॉलेज प्रबंधन ही अंतिम निर्णय लेता है। उधर, कॉलेज के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने बताया कि कुलपति ने जो आदेश दिया है, वह कोर्ट के दिए गए आदेश के हिसाब से अलग है। कुलपति के आदेश के बाद अब कॉलेज प्रबंध समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद कार्रवाई होगी।

शहर में चलेगा अतिक्रमण रोधी अभियान

गोरखपुर, (संवाददाता)। जलनिकासी व्यवस्था को सुचारु रखने, यातायात बाधाओं को दूर करने और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने शुक्रवार से 24 जुलाई तक विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत नगर निगम, पुलिस, यातायात पुलिस और प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम निर्धारित रूटों पर अभियान चलाकर सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएगी। नगर निगम ने अभियान का विस्तृत रूटवार कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। अभियान की शुरुआत तीन जुलाई शुक्रवार को रेलवे स्टेशन से सिंचाई डाकघर मार्ग से होगी। इसमें राजस्व, पुलिस, यातायात और नगर निगम की संयुक्त टीम 18 प्रमुख मार्गों पर कार्रवाई करेगी। इन सड़कों और फुटपाथों से अवैध कब्जे, ठेले–खोमचे और अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों को हटाएगी। जुर्माना भी वसूल करेगी। नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा है कि अभियान के दौरान सार्वजनिक भूमि, सड़कों, फुटपाथों और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। व्यापारियों एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लें, जिससे कार्रवाई की नौबत न आए। रेलवे स्टेशन से सिंचाई डाकघर, पैडलेगंज–ट्रांसपोर्टनगर, चटोरी गली गोलघर, शास्त्री चौक–नखास चौराहा, अग्रसेन तिराहा–बक्शीपुर चौक, बैंक रोड–तिवारी हाता, रुस्तमपुर–आजाद चौक, नखास–खूनीपुर, बक्शीपुर–मारवाड़ इंटर कॉलेज, पैडलेगंज–शास्त्री चौक, मोहद्दीपुर–कुनराघाट, जाफरा बाजार–मिर्जापुर चौराहा, शास्त्री चौक–हनुमान मंदिर, ट्रांसपोर्टनगर–मुंशी प्रेमचंद पार्क, अंबेडकर चौराहा–हरिओम नगर–मुख्य डाकघर तिराहा, नगर निगम गेट–बक्शीपुर चौराहा, विश्वविद्यालय चौक–महाराणा प्रताप मूर्ति और यातायात चौक से रेलवे स्टेशन रोड तक कार्रवाई की जाएगी। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से बृहस्पतिवार को पादरी बाजार और सूबा बाजार क्षेत्र में विशेष अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे, फुटपाथ और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। कुल लगभग दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और अन्य लोगों को दोबारा कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी गई। सहायक नगर आयुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। शुक्रवार से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

तीन माह में रिहंद बांध का जलस्तर 12.7 फीट घटा, बिजली उत्पादन की बढ़ी चिंता

वाराणसी, (संवाददाता)। सोनभद्र जिले के कैचमेंट क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से रिहंद बांध का जलस्तर तीन महीनों में 12.7 फीट घट गया है। इस वर्ष

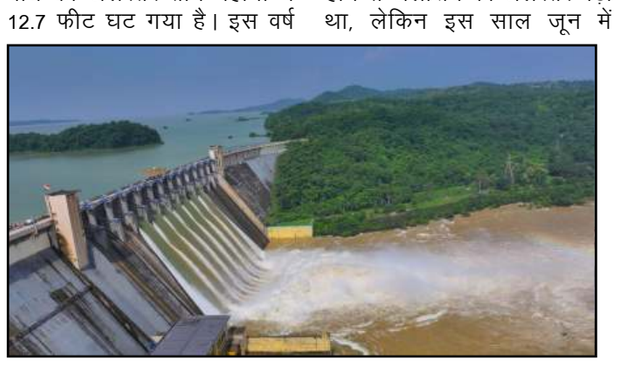

जुलाई में बांध का जलस्तर 842.8 फीट है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 846 फीट था। पिछले दो साल में जून के अंत तक कैचमेंट क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से जलाशय का जलस्तर बढ़ा था, लेकिन इस साल जून में अपेक्षित बारिश नहीं होने से स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। यदि आने वाले दिनों में सामान्य से कम बारिश हुई तो इसका असर तापीय विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन पर पड़ सकता है। भीषण गर्मी में बिजली की रिकॉर्ड मांग के कारण ऊर्जांचल की तापीय परियोजनाओं पर उत्पादन का स्तर बरकरार रखने का भारी दबाव रहा। प्रदेश में मई महीने में पहली बार बिजली की मांग 30 हजार मेगावाट के आंकड़े को पार कर गई थी। मांग को पूरा करने के लिए रिहंद जलाशय से लगातार पानी छोड़ा गया, जिससे जलस्तर में गिरावट आती रही। आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत में रिहंद का जलस्तर 855.4 फीट था। मई की शुरुआत में 852.5 फीट, जून की शुरुआत में 848.1 फीट और जुलाई के आरंभ है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।